women will be getting employment. Will the Government amend this Act to include this weaver community of women of our region?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हम बार-बार सदन को जानकारी दे रहे हैं और देना चाहते हैं कि कानून में कम से कम 33 फीसदी महिलाओं की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, श्रीमती वृंदा कारत जी बैठी हुई हैं, जोर लगाकर के कानून में हुआ कि कम से कम तिहाई भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए लेकिन हमें सदन को सूचना देते हुए खुशी है कि 42 फीसदी महिलाओं की भागीदारी है। इसलिए माननीय सदस्य कैसे कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हो ...(व्यवधान)...

श्री कुमार दीपक दास: मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं असम और नॉर्थ-ईस्ट की पोजीशन कह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अब खास रीजन या स्टेट और जिलों में कमोवेश का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 42 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। कोई खास राज्य में, खास जिले में कमी होगी, उसको हम लोग देख रहे हैं। फिर आपने बुनकर आदि का कहा है, तो इसमें बुनकर और गैर-बुनकर आदि का भेद ही नहीं है। जो कोई भी NREGA में काम करने की इच्छा रखते हैं, वे आवेदन करेंगे, उनको काम दिया जाएगा, कोई रोक-टोक नहीं है।

श्री कुमार दीपक दास: ऐसा रोक है।

MR. CHAIRMAN: Please don't ask the other supplementary. ...*(Interruptions)*...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: लेकिन बुनकर द्वारा बुनकरी करने के लिए, इसमें अभी तक बुनकरी का हमारे यहां प्रावधान नहीं है क्योंकि कहीं कोई सरकारी काम बुनकरी का नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें फिजिकल लेबर, मेहनत वाला काम है, अभी कला और स्किल्ड लेबर के लिए नहीं है।

Designing of software by TCS on NREG programme

*523. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a specially designed software has been prepared by Tata Consultancy Service Social Sector team, which helps in tracking every detail in NREGA Scheme;

(b) whether it is also a fact that this software has been successfully used in Andhra Pradesh to prevent misuse of funds meant for implementation of NREGA Scheme;

(c) if so, the details of the said software; and

(d) what steps Government propose to take to use this software in the entire country?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Government of Andhra Pradesh with the help of Tata Consultancy Services, (TCS), has developed a software for the Government of Andhra Pradesh to monitor the State Government's implementation of NREGS in the State. As reported by Government of Andhra Pradesh, this software has enabled the State Government to elicit data on the implementation of the programme in Andhra Pradesh as per the State Government's requirement. However, the TCS software used by the Government of Andhra Pradesh does

not capture data on critical statutory parameters such as the date of registration, household photograph on the Job Card, employment application date, dated, receipt against employment demand, daily attendance on muster rolls. Government of Andhra Pradesh has been advised to prepare a bridge software so that its TCS software may be enabled to generate data on National templates of the Ministry of Rural Development's website.

NREGA is a National Act and programme and the data has to be captured on standardized comprehensive parameters which are applicable across the country and subserve the non-negotiable statutory requirements of the Act. As such, the Ministry has already through NIC developed the National Software for NREGA, viz. *nregasoft*. The NIC software supports the operation of the computer based Management Information System (MIS) for NREGA, *www.nrega.nic.in* at the transaction level. It has been carefully designed, keeping in view the statutory requirements of the National Rural Employment Guarantee Act. It enables a detailed household based tracking of all physical and financial aspects of implementation. It places all data in public domain and infuses transparency in programme implementation. It also generates analytical reports and alerts for States to closely monitor the processes of the Act and fund utilization. The NIC software for NREGA has won awards, *viz.*, (a) Microsoft e-Governance Award, 2006 (b) Skoch Challenger Award, 2007 (c) Dataquest e-Governance Champion Award, 2008.

All the States are already using the NIC software with the exception of Andhra Pradesh. In a two-day National Workshop on MIS for NREGA on 28-29, December, 2007 all States IT Teams confirmed the high quality of the national software of NREGA built by NIC in the Ministry of Rural Development.

The MIS software developed by the Ministry has been through NIC, a Government organization. The software is fully owned by the Ministry and its maintenance is cost effective. It serves the purposes of the National Act in all its parameters. In contrast, the TCS software being used by Government of Andhra Pradesh has been developed by a private sector organization that retains the copyright for it. The maintenance of the TCS software is costlier, and information on all aspects of NREGA is not captured by it. Therefore, the question of using TCS software in the entire country does not arise.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: माननीय सभापति महोदय, जैसा इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि NIC ने NREGA का सॉफ्टवेयर डवलप किया है, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, कि जो इन्होंने डवलप किया है, वह जो आंध्र प्रदेश वालों ने टाटा कन्सलटेन्सी को दिया, यह उससे पहले किया गया था, या बाद में किया गया था? क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि सारे प्रांतों को इसके बारे में बोल दिया है और उनका डाटा इनके पास आता है। मैं यही जानना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश का सॉफ़्टवेयर पहले था, या केन्द्र सरकार के इनके मंत्रालय ने पहले इसे डवलव किया था?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जब NREGA कानून बना और कानून बनने के बाद जब हमने लागू किया, तो जो NIC सरकारी संस्था है, उन्होंने मुस्तैद होकर अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, जो देश भर के सभी राज्यों में लागू हो रहा है। उसी समय फिर TCS ने अलग से फिर कोई सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिसको आंध्र प्रदेश सरकार ने लागू किया है। यह आंध्र प्रदेश सरकार की अपनी इच्छा है। तो कोई भी राज्य सरकार अपनी इच्छा पर है, कहीं से वह लागू करे, लेकिन NIC का जो सॉफ्टवेयर है वह भी अच्छा है और वह देश भर में लागू किया गया है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि यह सॉफ्टवेयर डवलप करने के लिए जो पैसा है, वह क्या NRGEA से गया है या मिनिस्टरी ने इसके लिए अलग से खर्च किया है? और, जो आंध्र प्रदेश ने प्राइवेट कंपनी से लिया है, उसको उसने कहां से पैसा दिया है? दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि इनके पास सभी का डाटा और ट्रांसपेरेंसी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि कौन-कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं, जिनके पास इनका डाटा आया है, जो NREGA

में अपने टारगेट से अभी भी पीछे है। और जो उनको लागू नहीं कर सकीं, उन स्टेट्स के लिए मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय NREGA लागू करने में चार फीसदी establishment cost मंजूर है, जो स्थापना का खर्चा है, वह लगभग चार प्रतिशत है। उसी में से कोई राज्य सरकार, उसी 4 प्रतिशत में से चाहे टाटा कंसल्टेंसी से कराए या एन०आई०सी० से कराए, उनको उसी में से राशि मिलती है। इसलिए उसमें कोई भेदभाव और इधर-उधर का सवाल नहीं है।

दूसरा, माननीय सदस्या ने पूछा कि कौन-कौन से राज्यों से डाटा आ रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि सभी राज्यों से यह डाटा आ रहा है, इसलिए तो माननीय सदस्य जब पूछते हैं, तुरंत हम जवाब दे देते हैं।, जब डाटा हमारे पास नहीं रहता था, मेन्युअली होता था, तब मई, 2005 या जून, 2006 की रिपोर्ट आती थी, हम नहीं बता पाते थे, लेकिन अब महोदय, मंथली प्रोगैस रिपोर्ट आ रही है। इसलिए कुछ दिन पहले हम तीन करोड़ बीस लाख बता रहे थे, आज तीन करोड़ सैंतीस लाख बता रहे हैं, चूंकि मंथली प्रोगैस रिपोर्ट आ रही है और ई गवर्नैंस के माध्यम से ऐफिशिएंसी आई है। इसलिए अद्यतन सूचीं और काम का ब्यौरा हमको मिलता रहता है। सभी राज्यों में वह फंक्शनल है और सभी राज्यों से हमको डाटा आ रहा है, इसी आधार पर हम सदन को हर सत्र में अवगत कराते रहते हैं कि क्या स्थिति है और सदस्य जो सवाल पूछते हैं, हम तुरंत जवाब तैयार रखते हैं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, मैंने इनसे सवाल पूछा था कि जो राज्य NREGA में ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति ये क्या कदम उठा रहे हैं? इनके पास मंथली डाटा आता होगा, उसकी मॉनिटरिंग जब ये करते हैं, तो जो राज्य NREGA में ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उन स्टेट्स के लिए ये क्या कदम उठा रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, यह मैं जानना चाहती हूं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, बहुत बड़ा देश है और रंग-बिरंग की हुकूमत देश में चल रही है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: यह क्या मतलब हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभी को बुलाकर, उनको समझाकर, उनकी कहां कमजोरी है, उनकी सहायता करके, सभी तरह से ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: बिहार में किस रंग की हुकूमत है, यह भी बता दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में आपकी, NDA की हुकूमत है, जो लड़खड़ा रही है, मारा-पीटी, कहा-सुनी, झगड़ा-विवाद चल रहा है, इसको निकालो, इसको निकालो।

महोदय, federal structure of political system काम कर रहा है। इसलिए, सभी राज्यों से हमको सहयोग लेना है औ सभी राज्यों को हमें सहयोग देना है, समर्थन और सहायता करनी है। यह भी मैं बताने वाला हूं NDA के राज में राज्यों की जितनी भी सहायता हुई, उससे चार गुना, पांच गुना ज्यादा UPA के समय में राज्यों की सहायता हो रही है और हरेक मुख्य मंत्री से यह पूछा जा सकता है कि हम अधिक सहायता कर रहे हैं या NDA की हुकूमत जब दिल्ली में थी, उस समय अधिक सहायता हुई। इसलिए मुल्क के मालिकों के नाम हम सारा हिसाब-किताब देंगे और सदन में भी हम हिसाब बताएंगे कि किसके समय में कितनी ज्यादा सहायता हुई।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: In a scheme like this, if it is to be successful, then, one has to monitor and supervise misuse of funds at various levels. It is obvious. I would like to know that since the process of implementation of this programme has been started, whether any State Government has detected any misuse of funds and has filed prosecution against the culprits

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, 2,38,000 पंचायतें देशभर में हैं और 600 जिले हैं। जहां-तहां से कतिपय शिकायतें आती रहती हैं, उन पर हम राज्य सरकारों को सावधान करते हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं। इसलिए यह कहना कि देशभर में यह जहां भी लागू हो गया, वहां सभी लोग सत्यवादी हरीश चन्द्र हो गए, गांधी जी के शिष्य हो गए, ऐसा

नहीं है। जहां-कहीं भी जानकारी के बिना या नियम की भी खराबी पकड़ी गई है, वहां कार्रवाई की गई है। इसलिए उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं और मैं समझता हूं कि वर्ष, दो वर्ष में zero tolerance towards corruption की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि teething trouble, शुरुआती कठिनाई हो सकती है, वह हम मानकर चलते हैं। इसलिए हम मुस्तैद हैं और राज्य सरकारों से बराबर इंटरेक्शन हो रहा है, जिला स्तर पर हो रहा है, इसमें सुधार की प्रक्रिया जारी है। CAG को, महोदय, हमने कहा है कि आप जांच कीजिए।

श्री शान्ताराम लक्ष्मण नाबक: कितने केसिस हुए यह बताइए?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, देश भर में राज्यवार करीब 20-22 शिकायतें आई हैं, उन पर कार्यवाही हो रही है, जांच हो रही है।

श्री बृजभूषण तिवारी: सभापति जी, माननीय मंत्री जी बार-बार सदन में इस बात की घोषणा करते हैं कि इसमें transparency है और उन्होंने कहा की हमने NIC के जरिए जो software बनाया है, उसमें अद्यतन, up-to-date उसकी सूचना रहती है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि NREGA के बारे में जमीनी हकीकत यह है कि इसमें अधिकारियों का दखल बेहद बढ़ गया है और पंचायतों या जिला-परिषद की कार्य-योजना के आधार पर काम करने के बजाय, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यह सारा काम विभागों को सौंप दिया है और उसमें 21 परसेंट, 20 परसेंट, 25 परसेंट अग्रिम कमीशन लिया जा रहा है। क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है और यदि है, तो वे इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, मैंने शुरु में ही कहा कि राज्य सरकारों द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन होता है, हम केवल उसकी देखरेख, निगरानी, advise, coordination आदि का काम करते हैं और उनको अपने सुझाव तथा सलाह देते रहते हैं। यदि कोई खास specific शिकायत हो, तो वे बताएं। हो सकता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही हो, आप उसकी जानकारी हमें दीजिए, हम उसकी छानबीन राज्य सरकार से कराएंगे।

श्री बृजभूषण तिवारी: उत्तर प्रदेश में यह बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है और मेरे जिले सिद्धार्थनगर, बस्ती, इन सभी जगहों पर इस प्रकार की शिकायतें हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: किसी प्रदेश या किसी खास जिले में यदि उस तरह की शिकायत है, तो माननीय सदस्य हमें सूचित करें, हम जरुर उसकी छानबीन करेंगे, कार्यवाही करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए इस योजना में सदस्यों की भागीदारी, निगरानी और जानकारी की हमें अपेक्षा है। माननीय सदस्यों से हमारी प्रार्थना है कि वे जरूर इसकी देखरेख करें और इसकी देखरेख करके, मंत्रालय को जानकारी दी जाए, जिससे हम कार्यवाही कर सकें।

श्री बृजभूषण तिवारी: मंत्री जी, मैं आपको इस बारे में लिखकर जानकारी दूंगा।

श्री प्रकाश जावडेकर: सभापति जी, ये जो 2 softwares की बात चल रही है, 2 softwares में मुद्दा यह है कि NIC complies more on statutory norms and the TCS complies more on transparency norms. Can't the Government take initiative to have best of both because software development is a continuous process? उस पर सरकार क्या सोच रही है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, दोनों का interaction हुआ है और दोनों में bridge बनाने के लिए TCS को और राज्य सरकार को सुझाव भी दे दिए गए हैं। देश के पैमाने पर एक ढंग का काम हो, इसके लिए हमने प्रयत्न किया है।

श्री प्रकाश जावडेकर: मेरा सवाल उलटा है कि जैसे आपने आंध्र प्रदेश सरकार को कहा है कि bridge software तैयार करो, मैं केन्द्र सरकार से कह रहा हूं कि वह क्यों न उस software की अच्छी बातें उसमें ले, इससे देश भर को फायदा होगा। Transparency compliance is what is needed in NREGS. आप जो उनको bridge software बनाने के लिए कह रहे हो, आप वह काम यहां क्यों नहीं करना चाहते हैं, ताकि best of both मिल सके?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, एक तो यह देश भर के सभी राज्यों में लागू है और इसके लिए बड़ा नेटवर्क तैयार है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अलग से TCS का software इस्तेमाल किया। दोनों के बीच में interaction

हुआ और उसमें कुछ कमियां पाई गई, इसलिए यह तय हुआ कि इसका bridge software तैयार किया जाए। उसमें यदि वे हमसे सहायता चाहेंगे, तो हम NIC को कहेंगे, उस तरह से हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

* 524. [The questioner Shri Shahid Siddiqui was absent. For answer *vide* page 20 Infra]

Inspection Report of Admiral Gorshkov

*525. SHRI M.V. MYSURA REDDY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the inspection of Admiral Gorshkov which was to be completed by March, 2008 is over;

(b) if so, the details of inspection report;

(c) whether it is a fact that Russia has made it clear to the Ministry that cost escalation of Admiral Gorshkov is a must; and

(d) if so, what is the price escalation Russia has proposed and to what extent Government has agreed to give?

* 524. [The question (s) Shri Shahid Siddiqui was absent. For answer *vide* page .....Infra]

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Russian side submitted a revised Master Schedule indicating a delay in the project and an increase in price for repair and re-equipping of aircraft carrier ex-Admiral Gorshkov. The Russian side has indicated revision in time and cost due to 'Growth of Work'. The price escalation proposed by the Russian side is US Dollar 1202 million. The process of examination of the scope and necessity for additional work projected by the Russian side has been initiated.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, as per the Minister's reply, the escalation proposal by Russia for completion of Gorshkov is 1,202 million US dollars. This is nothing but breach of contract. When the contract was signed, it was a fixed-price contract and there is no clause for renegotiation in the agreement. Now, Russia is saying that substantial price rise is inescapable and we are examining on this which does not exist at all in the original contract. Sir, by supplementary is, after our specialised team inspection of the warship, whether it is true that Russian team is visiting India to sign a modified contract with revised price of Gorshkov. In that event, the Government of India might have made up its mind about the contract. I wish to know how the Government is planning to manoeuvre through this contract and clinch the deal in favour of India without breach of contract.

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Sir, the contract allows for growth and scope of work which has been submitted by the Russian side, and a Technical Evaluation Committee is examining the proposals. And, as and when, the examination is completed regarding the growth and scope of work and the necessity for the growth of work, a decision will be made on that.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, the growth of work is a pretext. It is learnt that in the new Russia, the defence exports are handled by ROSOBORON Export. This organisation is an autonomous organisation and profit is its sole motive and is not tied down by any strategic issues. I want to know from the Minister if it is a fact that this organisaiton is handling the Gorshkov deal. Is there any proposal before the Government to convince the